



कीनिया के सुम्बुर लोगों का एक गांव है उमोजा, जहां सिर्फ महिलाएं रहती हैं। उमोजा महिलाओं की शरण स्थली है, कोई भी महिला यहाँ रह सकती है लेकिन, पुरुषों पर प्रतिबंध है। सुम्बुर परंपरा के अनुसार मंगनी के बाद पुरुष अपनी मंगतरा को मनके भेंट करता है, जिससे वो अपने लिए हार बनाना शुरू कर दे। जितने अधिक सुंदर और अलंकृत मनके व उनसे बनने वाले हार होते हैं उतनी ही अधिक उसके पति की सम्पत्ति मानी जाती है। इन हारों को "मपोरो" कहते हैं। पर उमोजा गांव की महिलाओं के लिए यह हार शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि, उन्हें अब इस हार के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं होती, ये महिलाएं खुद कमाती हैं और स्वयं ही अपने लिए मनके खरीदती हैं व हार बनाती हैं। सैन्ट्रल कीनिया के इस छोटे से गांव की स्थापना, चित्र में नजर आ रही रिबेका लोलोसोली ने की है। उसने दशकों पहले सी-पुरुष समानता की लड़ाई शुरू की थी। उसे भी अपने पति से "एम्पोरो" मिला था। लेकिन विवाह के बाद पति के हाथों उसे भारी उत्पीड़न सहना पड़ा। वो बताती हैं, यहां पत्नी को पीटना मर्दानगी माना जाता है, "मेरा पति भी मुझे पीटा था, लेकिन, मैंने जवाब दिया। मैंने महिलाओं से कहा कि हमें यह सब सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे और पीटा गया, अंततः जब कोई विकल्प नहीं बचा तो मैंने घर छोड़ दिया।" लोलोसोली की हिम्मत ने उसे "उमोजा" बसाने की प्रेरणा दी। उमोजा का स्वाहिली भाषा में अर्थ है "एकता"। लोलोसोली ने 14 महिलाओं की मजबूत टीम के साथ शुरूआत की। उसका लक्ष्य था महिलाओं के लिए स्वायत्तता और अधिक आत्मनिर्भरता पाना। जल्दी ही इस गांव के बारे में सब तरफ चर्चा फैल गई। पुरुषों की हिंसा से पीड़ित महिलाएं सुरक्षा के लिए दूर-दूर से यहां आने लगीं। आज उमोजा में 50 घर, बच्चों के लिए स्कूल और आधुनिक सैनिकी सुविधाएं हैं। लोलोसोली कहती हैं, हमारा लक्ष्य है, "हमें इतनी कमाई हो कि हम अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए भेज सकें।" इस गांव को विभिन्न चैरिटी संस्थाओं से मदद मिलती है। इसके अलावा महिलाएं पारंपरिक नैक्लेस "एम्पोरो" बनाकर बेचती हैं, जिनकी कीमत 5 से 60 डॉलर तक होती है और इनसे अच्छी कमाई हो जाती है।

सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में दिल्ली व पंजाब के नेताओं ने आप से गठबंधन पर खुलकर विरोध जताया

अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है, वहां प्रचार करके भाजपा को आप सीधी मदद क्यों पहुँचा रही है

हैदराबाद, 17 सितम्बर। इण्डिया गठबंधन में दलों के भीतर अलग-अलग राज्यों में सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस के लिए दिल्ली और पंजाब को लेकर यह मसला सिरदर्द बनता जा रहा है, जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है। सोनिया गांधी ने हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) की बैठक के पहले दिन इंडिया ब्लॉक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, 2024 में बीजेपी के खिलाफ जीत के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ना जरूरी है।

सोनिया गांधी के बयान से साफ है कि, सोनिया गांधी गठबंधन की ताकत जानती हैं। 2004 में यूपी.ए. गठबंधन ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अजेय माने जाने वाले नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस को सत्ता से बाहर कर दिया था।

लेकिन वर्तमान में स्थिति उस

गौरतलब है कि, सोनिया गांधी ने सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक शुरू होने से पहले यह बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि, कांग्रेस इण्डिया गठबंधन को कांग्रेस पूरी अहमियत देगी। गौरतलब है कि, सोनिया गांधी ने कहा है कि, सभी दलों को एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करना होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली और पंजाब के नेताओं की चिंताओं को ध्यान से सुना और उन्हें स्वीकार भी किया। हालांकि, उन्होंने पार्टी नेताओं का आश्वासन दिया कि, आगे कोई भी फैसला स्टेट यूनिट से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा।

समय से काफी भिन्न है, तब कांग्रेस लीड करने की स्थिति में थी। वह फैसले ले सकती थी और दूसरे दलों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दबाने में भी सक्षम रही। ब्रिजिद मुनेत्र कड़गम (डी.एम.सी.) और तुणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) जैसे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के तहत काम करके खुश नजर आते थे। उस दौरान यूपी.ए. के भीतर बगवती सुर कम ही सुनाई देते थे।

अब जब समय बदल गया है और क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता आप की बढ़ती ताकत है। दिल्ली बिल

को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने आप का साथ दिया था। इसके बावजूद की इस समर्थन को लेकर विरोध की आवाजें उठी थीं। साथ ही जो लोग ऐसे किसी भी गठबंधन के खिलाफ थे, आखिरकार उन्होंने भी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। हालांकि, सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में इस स्वीकृति पर मतभेद की बात सामने आई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के लिए हैदराबाद को इसलिए चुना गया क्योंकि पार्टी को यकीन है कि वह भारत राष्ट्र समिति को हरा सकती है। लेकिन, कांग्रेस गठबंधन को लेकर प्रतिबद्धता के बावजूद आप से असहमति की आवाज को नियंत्रित नहीं कर सकी।

पंजाब और दिल्ली के कुछ नेताओं ने यह मुद्दा उठाया। इनका कहना था कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप के साथ किसी भी गठबंधन के खिलाफ पुरजोर वकालत करने वाले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान में खराब प्रदर्शन वाले कांग्रेस विधायकों के टिकट कटेंगे

सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में राजस्थान चुनाव में पार्टी की एकता पर जोर दिया गया

-लक्ष्मण वैकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 सितम्बर।
हैदराबाद में दो दिवसीय सी.डब्ल्यू.सी. की मीटिंग के लिए एकत्रित हुए कांग्रेस नेतृत्व ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन

सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट को हाईकमान ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि, केवल आगामी चुनाव में सरकार को रिपीट करने पर फोकस करें, नेतृत्व का मुद्दा चुनाव परिणाम आने के बाद तय किया जायेगा।

पायलट को निर्देश दिये हैं कि, वर्तमान में वे राज्य में सत्ता बरकरार रखने पर ध्यान केंद्रित रखें तथा नेतृत्व का मुद्दा चुनाव परिणाम आने के बाद तय किया जायेगा।

पांच राज्यों, राजस्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तेलंगाना तथा मिजोरम के शीघ्र होने वाले चुनावों पर विचार करने की प्रक्रिया में, कांग्रेस पार्टी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति में राजस्थान की चुनावी तैयारियों पर हुए गहन चिन्तन का सारांश यही है।

पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया कि, नेतृत्व ने राज्य इकाई से प्राप्त

विधायकों के टिकट कटने की संभावना है।

राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में जो एक चीज है, वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं द्वारा सरकार के पक्ष में पैदा की गई भावनाएं। वो इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाने में और इसका खूब प्रचार करने में सफल रहे हैं। अब, इसे पार्टी के लिए सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है।

लेकिन नेतृत्व ने ना केवल एक साथ मिलकर लड़ने की बात पर जोर दिया है, जैसा कि इस समय दिखाई दे रहा है, बल्कि यह भी कहा है कि, राज्य के दोनों बड़े नेता, अशोक गहलोत व पायलट, आपस में लड़ रहे भाजपा के विभाजित गुटों जैसी भद्दी तस्वीर प्रस्तुत करने के विपरीत, एकता की तस्वीर प्रस्तुत करें।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बागीदौरा में 15 व बांसवाड़ा में 9 इंच बारिश

बांसवाड़ा, 17 सितम्बर (निसं)। जिले में रिमझिम मुसलाधार बारिश आफत बनती नजर आ रही है। शनिवार को हुई तेज वर्षा ने जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। कई नदी-नाले उफान पर होने के चलते स्थिति हो गई है कई मार्ग अवरूद्ध हो चुके हैं।

बांसवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर स्थित लसाडा पुल पर शाम छह बजे तक 12 से 13 फीट ऊपर पानी बहता नजर

बांसवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर स्थित लसाडा पुल पर शाम छह बजे तक 12 से 13 फीट ऊपर पानी बहता नजर आया।

आया। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे नदी-नालों के पास नहीं जाएं। साथ ही टूटे बिजली के खंभे एवं तारों को देखते हुए सावधानी बरतें। इधर बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 15 इंच वर्षा बागीदौरा क्षेत्र में मापी गयी वहीं सबसे कम लोहारिया में दो इंच वर्षा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरपंच सहित तीन लोग नाले में बहे, तीनों की मौत

तीन किमी. दूर मिला सरपंच का शव, तीसरे का पता नहीं चला

बांसवाड़ा/डूंगरपुर (निसं)। आसमान से बरसी आफत की बरसात ने कुशलगाढ़ क्षेत्र के तीन लोगों की जान ले ली इसमें एक सरपंच भी शामिल है। क्षेत्र में दो दिनों से भारी वर्षा के चलते तालाबों पर चादर चल रही है वहीं नदी नाले उफान पर है।

बांसवाड़ा के माही डैम के सभी 16 गेट खोलने के 12 घंटे बाद डूंगरपुर का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम टापू बन गया है। धाम पहुंचने के तीनों पुलियों पर 15 से 20 फीट तक पानी बह रहा है। धाम पर मंदिर के पुजारी समेत 48 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं और उनके उठरने को लेकर भी धाम पर सभी व्यवस्थाएं हैं। वहीं, डूंगरपुर से बांसवाड़ा को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर भी 15 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। जिससे दोनों ही शहरों का सड़क संपर्क टूट चुका है। धाम पहुंचने व बांसवाड़ा-डूंगरपुर-उदयपुर जिलों को जोड़ने वाले के

बांसवाड़ा के माही डैम के सभी 16 गेट खोले, बेणेश्वर धाम टापू बना।

गनोडा-साबला व लसाडा-माही पुल पर पानी की भी 15 फीट चादर चल रही है।

साबला, वालाई और बांसवाड़ा पुल पर पानी का स्तर बढ़ने लगा है। रविवार को पुल पर 15 से 20 फीट पानी चल रहा है।

बाताया जाता है कि शनिवार शाम को डूंगरीपाडा पंचायत के 42 वर्षीय सरपंच दिनेश गरासिया पुत्र दला अपने घर नानीकासाथ से पंचायत भवन में रखी सीमेंट व्यवस्थित करने के लिये मोटर साईकिल लेकर घर से निकला था। घर से लगभग आधा किमी. दूर पंचायत भवन था लेकिन रास्ते में नाला था। देररात तक दिनेश के घर नहीं लौटने पर परिवारजनों को संदेह हुआ तो उसके पुत्र राकेश ने पुलिस को सूचना दी। उपखंड अधिकारी रामलाल मीणा,

तहसीलदार विरेन्द्र सिंह राठौड़, पुलिस उप अधीक्षक रुपसिंह राठौड़, सीआई रोहित कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। इधर आपदा राहत दल भी घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस दल ने नानीकासाथ के पास के नालों में खोजबीन की। नाले से लगभग 200 मीटर दूर दिनेश की मोटर साईकिल देखी गयी। इसके बाद आस-पास सघनता से जांच की गयी तो लगभग तीन किमी. दूर वागल मंदिर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में फंसा शव दिखाई दिया। उसकी पहचान दिनेश के रूप में की गयी। इसी तरह नगर से लगभग 16 किमी. दूर गांव भंवरकोट का अमर सिंह पुत्र हवसिंह डामोर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तानी ड्रोन ने पंजाब में 5.63 किलो हेरोइन गिराई

जालंधर, 17 सितंबर (वार्ता)। बी.एस.एफ. ने पिछले 24 घंटों दौरान पंजाब के सीमावर्ती जिलों से एक पाकिस्तानी ड्रोन और पांच किलो 6.30 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की है।

बी.एस.एफ. के प्रवक्ता ने बताया कि, सुरक्षा बल के जवानों ने पंजाब के सीमावर्ती जिला तरनतारन के गांव टी.जे. सिंह के पास एक संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि देखी, ड्रोन से 5.63 किलोग्राम हेराइन गिराई गयी।

बी.एस.एफ. के प्रवक्ता ने बताया कि, सुरक्षा बल के जवानों ने शनिवार को जिला तरनतारन के गांव टी.जे. सिंह के पास एक संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि को धांपते हुए उसे रोकने के लिए तुरंत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाटो अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करेगा

ब्रुसेल्स, 17 सितंबर (वार्ता)। नाटो शीत युद्ध के बाद 2024 में जर्मनी, पोलैंड और तीन बाल्टिक राज्यों में "स्टीडफास्ट डिफेंडर" नामक अपना सबसे बड़ा अभ्यास आयोजित करेगा। सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल रॉब बाउर ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल रॉब बाउर ने बताया कि, नाटो शीत युद्ध के बाद 2024 में जर्मनी, पोलैंड और तीन बाल्टिक राज्यों में "स्टीडफास्ट डिफेंडर" नामक अपना सबसे बड़ा अभ्यास आयोजित करेगा।

नॉर्वेजियन सशस्त्र बलों के प्रमुख एरिक क्रिस्टोफरसन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन बाउर ने कहा, 2024 में, गठबंधन शीत युद्ध के बाद से अपना सबसे बड़ा सामूहिक रक्षा अभ्यास (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष और कांग्रेस संसद सत्र में महिला आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से पेश करेंगे

सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं और सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर किये

हैदराबाद, 17 सितंबर (वार्ता)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि कांग्रेस कार्य समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) की मांग है कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। रमेश ने कहा कि रविवार को हुई सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में यह मांग की गई। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा।

सोमवार से लोकसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस बैठक में सभी विपक्षी दलों ने मांग की है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान

महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिया जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद यह जानकारी दी। एन.सी.पी. नेता और महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि उनकी पार्टी ने भी सरकार से यही मांग रखी है।

पटेल ने बताया कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर संसद को नए धवन में शिफ्ट किया जाएगा। विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने की मांग कुछ अन्य दलों ने भी की है। इन दलों में बी.जे.डी. और बी.आर.एस. का नाम

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद यह जानकारी दी। सोमवार से लोकसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस बैठक में सभी विपक्षी दलों ने मांग की है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिया जाए।

संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने की मांग कुछ अन्य दलों ने भी की है। इन दलों में बी.जे.डी. और बी.आर.एस. का नाम शामिल है।

जयराम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, कांग्रेस

लोकसभा द्वारा भी पारित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहली बार मई 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। यह लोकसभा में पारित हो गया लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में प्रस्ताव गिर गया।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने अप्रैल 1993 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान

संशोधन विधेयक फिर से पेश किया और विधेयक पारित हुआ तथा कानून बना। उन्होंने कहा कि अब पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। यह करीब 40 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री के रूप में, डॉ. मनमोहन सिंह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक लिए। विधेयक नौ मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया।